EMPOWRING PANCHAYAT & COMMUNITY TO ENSURE THEIR PARTICIPATION DURING PREPARATION OF PLAN UNDER MGNREGA IN JHARKHAND

The Department of Rural Development, Government of Jharkhand has awarded a project to Gramin Vikas Trust on preparation of Perspective Plan for the year 2013-14 to 2016-17 under Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). GVT has organized series of meeting at Village and Panchayat levels in different districts of Jharkhand with a view towards empowering the Panchayat for community participation in preparation of perspective plan under MGNREGA.

Dainik Bhaskar, West Singbhbum Edition has covered the news and published it on 12th July, 2013.

News clipping has been attached as a reference below.

केरा पंचायत बनेगा आदर्श पंचायत

गूड न्यूज सामूहिक सहभागिता से होगा भू संरक्षण का कार्य, पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होगी योजना

भास्कर न्यूज | चक्रधरपुर

पश्चिमी सिंहभूम जिले के 18 पंचायतों को आदर्श पंचायत बनाने की योजना का प्रारंभ केरा पंचायत से शुरू होगी। इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में चार साल की मेहनत लगेगी। जल संरक्षण व भूमि संरक्षण इस प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा होगा।

पंचायत के ग्रामीणों की सहभागिता से पूरे चार साल में लोकतंत्र का मूलमंत्र जनता के लिए जनता की तर्ज पर आदर्श पंचायत के तौर पर विकास किया जाएगा। पंचायत के ग्रामीणों को वैचारिक तौर पर गांव के विकास के लिए भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास ट्रस्ट संस्था को नामित किया गया है। इस महीने योजना का डीपीआर बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा।

इन पंचायतों को आदर्श गांव बनाने की योजना

आनंदपुर, ओटार, सिंबिया, केरा, कायदा, गुलीकेराजयपुर, बड़ानंदा, केलेंडे, रूइडी, कुमिरता, बड़ातोरलो, सोनापोस, कोलपोटका, बड़ापासेया, असनतलिया (सोनुवा) कासेया, नीमडीह।

शीघ्र शुरू होगा डीपीआर का काम

झारखंड का यह पहला पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें लोक भागीदारी से पंचायतों का विकास किया जाएगा। केरा पंचायत से डीपीआर बनाने की शुरुआत होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरे चार साल लगेंगे। जल संरक्षण व भूमि संरक्षण पर पंचायतों में विशेष कार्य होंगे। क्आदर्श पंचायत बनने के बाद इस पंचायत का विकास भी होगा। "

विनय कुमार सहाय, ग्रामीण विकास ट्रस्ट

It is felt that works under MGNREGS, while providing wage employment benefits to the rural population, should also contribute towards generation of long-term and productive assets, improvement in the quality of life and promotion of sustainable livelihoods.

A review of the schemes in Jharkhand reveals that almost 70% of the works taken up under MGNREGS are related, in one way or another, to water harvesting, water conservation, drought proofing and minor irrigation, etc., but these are being mostly taken up on an ad-hoc basis. A major component in this regard consists of dug wells on private plots. Apart from potential issues of sustainability, the dug wells component in the scheme has also been affected by the scheme guidelines pertaining to labour: material cost ratio of 60:40.

Given this background, and keeping in view the availability of heavy quantum of rainfall but minimal irrigation coverage in the state, a well planned and coordinated programme needs to be prepared and implemented under MGNREGS scheme. The Empowerment of Panchayat and Community for their Participation is the key objective for its success.